

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग  
\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन,  
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
दिनांक : 03 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

**विषय :-** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक मंहगाई भत्ते का भुगतान।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 तथा अनुबंध- III (ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय मंहगाई भत्ते की दरें दी गई हैं। मंहगाई की दरों में संशोधन की अगली किश्त दिनांक 01.01.2020 से देय है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को मंहगाई भत्ते की दरें निम्नलिखित रूप से देय हैं :

(क) जिस तारीख से देय है : 01.01.2020

(ख) सितम्बर, 2019- नवम्बर, 2019 तिमाही का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

सितम्बर, 2019	322
अक्तूबर, 2019	325
नवम्बर, 2019	328
तिमाही का औसत	325

(ग) मूल्य सूचकांक: 277.33 (दिनांक 01.01.2017 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 47.67 (325-277.33)

(ङ.) दिनांक 01-01-2020 से मंहगाई भत्ता दर : 17.2% [(47.67 + 277.33) X 100 ]

2. उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 17.2% औद्योगिक मंहगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(नरेश कुमार)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।  
प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(नरेश कुमार)  
अवर सचिव